special component plan for SCs in the State schemes (SCA-SCP-SCs);

(c) whether the "SCA-SCP-SCs" does not lost only to create two different agencies for the same targeted group as the objective could be achieved by reinforcing the fund under other development schemes; and

(d) what actions have been taken for checking fraud, withdrawal and to avoid overlapping of targeted families under different schemes?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The SC community suffered from and continues to suffer from below poverty line economic status, poor asset base, dependence on wage labour, subsistance farming, share cropping, unclean occupation with attendant social and civil disabilities. The Special Component Plan (SCP) strategy of the Government was evolved with the objective of overall development of SCs to bring them above the poverty line and into the mainstream life with equal social and economic status with other sections of the population. SC is envisaged to channelise the flow of outlays and benefits from the general sectors in the Plans of States and Central Ministries, at least in proportion to their population both in physical and financial terms. Special Central Assistance (SCA) is provided to States as an additive to their SCPs for Scheduled Castes. States have to utilise SCA funds in conjuction with their SCPs on economic development activities programmes for SCs under various sectors, particularly in the core sectors like agriculture, animal husbandry, village and cottage industries, sericulture, etc. SCA is to give an added thrust to family oriented schemes of economic development of SCs by providing vital missing inputs, so that schemes could be more meaningful. SCA is an important instrument for the poverty alleviation among SCs. The strategy of SCP itself implies development of SCs from all sectors of development in the Plans of States and Central Ministries. As such, the question of SCA leading to creation of two different agencies for the same target group does not arise.

(d) Through scrutiny of utilisation of SCA funds under various sectors/schemes is carried out through annual progress report on utilisation of SCA funds and physical achievements under the schemes, furnished by the State Govts. in prescribed proforma devised for the purpose. SC families economically assisted under Integrated Rural Development Programme (IRDP) and non IRDP are monitored under Point II A of Twenty Point Programme.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए फंडों का दुरुपयोग

2170. श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :
श्री अजीत जोगी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी राज्य की ओर से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रदत्त फंड के दुरुपयोग संबंधी कोई सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो दुरूपयोग की गयी राशि का राज्य-वारब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्ष 1991 से 1996 के दौरान राज्य सरकारों को आबंटित कोई धनराशि व्ययगत हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार को वर्ष 1996-97 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए और अधिक धन के आबंटन संबंधी कोई परियोजना/प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय के आदिवासी विकास प्रभाग में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की गई निधियों के दुरुपयोग के बारे में कोई मामला ध्यान में नहीं आया है, लेकिन कुछ मामलों में निधियों के विपणन के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

(1) वर्ष 1992–93 में व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करने के लिए मिजोरम सरकार को निर्मुक्त 14.75 लाख रुपये आइजल में वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए गए हैं।

(2) वर्ष 1993–94 में 3 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार को निर्मुक्त 44.34 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुधार के लिए उपयोग की गई है। दोनों राज्य सरकारों से इस राशि को वापस करने के लिए कहा गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रेस रिपोर्टों से इस मंत्रालय के अनुसूचित जाति प्रभाग के ध्यान में यह आया है कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निधियों के गबन के मामले रहे हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से इस मंत्रालय को ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) वर्ष 1996–97 के दौरान राज्य को स्वीकार सामान्य विशेष केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुदान के अन्तर्गत 2823.49 लाख रुपये की लागत का मध्य प्रदेश के जिला रायपुर में सड़कों/पुलियों तथा पुलों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। लेकिन चूंकि वर्ष 1996-97 से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ऐसे प्रस्तावों का वित्त पोषण समाप्त कर दिया गया है इसलिए सामान्य आबंटन के अतिरिक्त निधियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार राज्य सरकार को सूचित किया जा रहा है।

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Madam Deputy Chairman, I have given notice of privilege... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me finish "Papers to be laid on the Table" first; then, I will allow you. (*Interruptions*)...Let me finish this item, I will allow you.

I. **Report and Accounts (1995-96) of the Scooters India Ltd. Lucknow and related papers**

II. **Notifications of the Ministry of Industry**

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): Madam, I lay on the Table:—

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Twenty-fourth Annual Report and Accounts of the Scooters India Limited, Lucknow, for the year 1995-96, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.